भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4497
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

किसानों को वाई-फाई सुविधा का लाभ

4497. श्री सनातन पांडेयः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों के लाभ के लिए देश के सभी गाँवों में इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं ताकि वे कृषि क्षेत्र के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकें और कृषि क्षेत्र में हो रहे नए विकासों की जानकारी प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय/कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो देशभर के सभी गाँवों में इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) आरजीआई (भारत के महारजिस्ट्रार) के आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30.06.2025 तक देश के कुल 6,44,131 गाँवों में से 6,26,055 गाँवों में मोबाइल कवरेज नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा (3जी/4जी) उपलब्ध है।

(ख) और (ग) देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भारतनेट के माध्यम से देश में कुल 13,01,193 एफटीटीएच कनेक्शन चालू किए गए हैं। वाई-फाई प्रौद्योगिकी समर्थित एफटीटीएच कनेक्शन का उपयोग सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स आदि तक एक्सेस के लिए किया जा रहा है जिसमें किसानों द्वारा कृषि के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में हो रहे नए विकास के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए इसका उपयोग शामिल है।

गाँवों में मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत 4जी सेचुरेशन परियोजना, सीमा चौकी (बीओपी)-सीमा आसूचना चौकी (बीआईपी) परियोजना, भारतनेट परियोजना आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। 4जी सेचुरेशन परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत देश में 21,748 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

इसके अलावा भारत सरकार ने "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2022-23" नामक पुनःडिजाइन की गई और विस्तार की गई स्कीम वर्ष 2022-23 के लिए लॉन्च की है। पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2022-23 के भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए 3000 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गई हैं। इस निधियों का उपयोग सरकारी संस्थाओं (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केंद्र, डाकघर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थाओं और घरों तक भारतनेट नेटवर्क के माध्यम से ओएफसी पर अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (एलएमसी) प्रदान करने के लिए वर्तमान में भारतनेट का विस्तार कवर की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) से गावों तक करने के लिए किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएमवाणी) फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार करने के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन दिया है। वर्तमान में देश भर में 3,53,105 पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट संस्थापित किए गए हैं।

*****